

खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं, घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं : दिया कुमारी

बजट बहस का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर कटाक्ष किया

जयपुर (विसं)। उप मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने बजट बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बायतू से हरीश चौधरी, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा सहित अन्य सदस्यों द्वारा उठाए बिंदुओं का तलख जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि “खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं, घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं।” हमारी सरकार राजस्व आय में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस सरकार के वक्त राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का के 4.4 प्रतिशत था, जबकि हमारी सरकार की ओर से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2025-26 में 3.87 प्रतिशत अनुमानित किया। साल 2026-27 में कम करके 3.6 9 प्रतिशत अनुमानित है। दिया कुमारी ने सबसे पहले सड़कों के क्षेत्र में घोषणा करते हुए कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मरम्मत व उन्नयन के लिए 690 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। डीएमआईसी नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में 1012 करोड़ रूपए की लागत से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

कृत्रिम जलाशय व फीडर निर्माण पर अगले साल 200 करोड़ रूपए खर्च होंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन बदलने के लिए 150 करोड़ खर्च होंगे। वहीं, विद्याधर नगर में पानी की पाइप लाइन, टंकी



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को सदन में बजट बहस का जवाब दिया।

निर्माण व टचयूबवेल के लिए 37 करोड़ रुपए की घोषणा की।

‘किसानों को खेत तक रास्ता देगी सरकार’

किसानों को खेत तक रास्ते के लिए 20 फीट तक सरकारी जमीन की पट्टी का आवंटन हो सकेगा। इसके लिए डीएलसी की दुगुनी दर से पैसा देना होगा। दिया कुमारी ने कहा कि

रास्तों और खातेदारी जमीन के बीच में सरकारी भूमि होने पर अप्रोच रोड-पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसी खातेदारी जमीन का गैर कृषि कार्यों में उपयोग के लिए लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता। ऐसे प्रकरणों में 20 फीट तक की चौड़ाई की सरकारी जमीन की पट्टी का कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की दुगुनी दर से भुगतान करने पर संबंधित खातेदार को अप्रोच रोड-पहुंच मार्ग के लिए आवंटन आवंटन किया जा सकेगा।

■ कांग्रेस सरकार के वक्त राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का के 4.4 प्रतिशत था, जबकि हमारी सरकार की ओर से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2025-26 में 3.87 प्रतिशत अनुमानित किया। साल 2026-27 में कम करके 3.6 9 प्रतिशत अनुमानित है।

‘हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली’

दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। विपक्ष की तथ्यात्मक आलोचना का हम स्वागत करते हैं। कुछ ने अनावश्यक अर्नागल आलोचना की, मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कम से कम बजट तो पढ़ा। यह तो इनकी परंपरा रही है। बजट समझा भले न हो, लेकिन पढ़ तो लिया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी नेता प्रतिपक्ष ने आज अनजाने ही सही हमारे पिछली बजट की तारीफ कर दी। आज उन्होंने कविताओं के अलावा ज्यादा कुछ आलोचना करने को मिला नहीं।

‘मेरा पानी पीना याद रहा, जेजेएम में भ्रष्टाचार नहीं’

दिया कुमारी ने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि लक्ष्मणगढ़ विधायक ने मेरे बजट भाषण पढ़ने के दौरान मेरे द्वारा सात आठ बार पानी पीने पर टिप्पणी की। अब क्या करें, हमारे समय में पानी आसानी से सब लोगों के लिए उपलब्ध है। अब आपके समय में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में जो भ्रष्टाचर हुआ वो सब जानते हैं। उनकी सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर तो इनका ध्यान गया ही नहीं, पर मैंने कितना पानी पिया उस पर ध्यान जरूर जाएगा। अभी मैं पानी और पी लेती हूँ। यह कहकर दिया कुमारी ने गिलास उठाकर पानी पीया। इस पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि पानी बर्बाद क्यों किया जा रहा है इतनी सी बात है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पानी पीने को बर्बाद करना कैसे कह सकते हैं।

‘एक लाख पदों पर भर्ती प्रोसेस में है’

दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को नौकरियां दे रही है। एक लाख पदों पर भर्ती प्रोसेस में है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी है।

बजट बहस के जवाब में सरकारी कर्मचारियों को लुभाया

ट्रेनिंग में नौकरी छोड़ने पर वेत्तन भत्तों की नहीं होगी वसूली

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए प्रदेश के बुनियादी विकास, कर्मचारी और आमजन हित में कई अहम घोषणाएं कीं। दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग के दो साल की अवधि में केंद्र या राज्य की दूसरी नौकरी में चयन पर मौजूदा पद छोड़ने पर राहत देने की घोषणा की है। अब दो साल की ट्रेनिंग अवधि में पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सटेंडेट इश्योरेंस मेच्योरिटी के साथ अर्धवार्षिक रिटायरमेंट तिथि तक इश्योरेंस कवर दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान को पोछे किसने छोड़ा था, यह इतिहास जानता है। शिक्षा, कृषि पर नेता प्रतिपक्ष ने बजट कम करने की बात उठाई। हमारा कृषि बजट कांग्रेस सरकार से 34 प्रतिशत ज्यादा है। कम से कम आंकड़े तो सभी रख दीजिए। दिया कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय औसत दर से हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा होने पर विधायक ने सवाल उठाए। हमारा फेडरल

स्ट्रक्चर है। राजस्थान की जीएसडीपी की ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने में राजस्थान ग्रोथ इंजन का काम करेगा। राज्य की जीएसडीपी अगले साल तक 21 लाख करोड़ पार होने का अनुमान है। यह कांग्रेस राज से 41 प्रतिशत से ज्यादा है।

बजट रिप्लाय में राहत, छोटी छोटी घोषणाओं से लुभाया

-किसानों को खेत तक पहुंचने के लिए जमीन देगी सरकार -कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र -शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए 690 करोड़ की घोषणा -ट्रिपल आईटी कोटा में नए कोर्स होंगे शुरू, एआई हब बनेगा -लूणकणसर में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया -75 हजार स्कूली बच्चों की आंखों की जांच कर देंगे चश्मे

‘गौ-हत्या’ पर विधानसभा में दिनभर हंगामा, 7 बार कार्यवाही स्थगित

विपक्ष के आरोपों से गुस्से में आकर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा वैन क्रॉस करके विपक्ष की तरफ जा पहुंचे, हाथापाई की नौबत बनी

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। ‘गौ-हत्या’ के मुद्दे पर विधानसभा में मंगलवार को करीब 6 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। मामला इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही भी 7 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने पिछले सप्ताह जयपुर में गौहत्या की हत्या को लेकर हंगामा किया। कांग्रेसी विधायकों ने सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा पर गौ-हत्याओं को बचाने तक का आरोप लगा दिया, जिससे आवेश में आकर विधायक गोपाल शर्मा वैन क्रॉस करते हुए विपक्ष की तरफ जा पहुंचे। इस दौरान हाथापाई की नौबत तक आन पड़ी थी। बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस विधायक, सिविल लाइंस गोपाल शर्मा को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की तैयारी में है। विपक्ष ने मांग की है कि गौ-हत्या की जांच की जाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

दिनभर के हंगामे के बाद शाम करीब 5 :15 बजे स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दोनों पक्षों को शांत किया और उनका पक्ष सुना। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि, प्रश्नकाल के दौरान गाय को “गुज्य माता” का दर्जा देने से जुड़े सवाल पर जवाब के दौरान सदन में माहौल गर्माया। पिछले दिनों जयपुर में गौ-हत्या का पाप हुआ है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रश्नकाल में जब यह मामला उठा उस वक़्त भाजपा विधायक गोपाल शर्मा आवेश में आकर गुस्से में विपक्ष की तरफ आ गए थे। हम गोपाल शर्मा

■ करीब 6 घंटे के हंगामे के बाद शाम 5:15 बजे स्पीकर ने बीच बचाव किया और कहा कि “रिकॉर्डिंग और कागज देखकर फैसला करेंगे”

के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे। इस पर सरकारी मुख्य सचिवत जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इशारा करके गोपाल शर्मा को गौ-हत्यारा कहा था, तब माहौल गर्माया था। गोपाल शर्मा पर विशेषाधिकार आण्णा तो राजाखेड़ा विधायक के खिलाफ भी आना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। इस पर टीकाराम जुली ने कहा कि, दोनों अलग-अलग प्रकरण है, लेकिन सत्ता पक्ष का यह कहना गलत है कि, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आण्णा तो राजाखेड़ा के विधायक के खिलाफ भी आण्णा। अगर आसन को राजाखेड़ा विधायक के खिलाफ कार्यवाई करनी है तो करें, लेकिन उस प्रकरण को इस मुद्दे से नहीं जोड़ें।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही

के दौरान और स्थगित करने के बाद हुई घटनाओं के वीडियो रिकॉर्डिंग, उपलब्ध दस्तावेजों और अधिकारिक अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद इस प्रकरण का फैसला किया जाएगा। देवनानी ने कहा कि सदन लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और उसकी गरिमा बनाए रखना प्रत्येक सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान हुई तथा उससे पूर्व हुई सभी घटनाओं की निष्पक्ष समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद विधानसभा में गतिरोध खत्म हो गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली का भाषण शुरू हुआ। इसके बाद दिनभर चला गतिरोध टूटा।

दरअसल यह हंगामा उस वक्त हुआ, जब भाजपा विधायक बालमुकुंदराचार्य ने गाय को राज्यमाता का दर्जा देने और गौवंश तस्करि से जुड़ा सवाल पूछा था। जिसके जवाब में गोपालन मंत्री ने कहा कि गौ-हत्या रोकने कानून बना हुआ है। इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में हुई “गौ-हत्या” के प्रकरण को लेकर हंगामा किया और पोस्टर भी सदन में लहराए। नेता प्रतिपक्ष जुली ने कहा था कि, पिछले सप्ताह जयपुर में ही गौहत्या हुई। हिंगोनिया गौशाला से गाय का सिर काटकर लाए, बीजेपी नेता का उसमें नाम है, उसे बचाने की कोशिश हो रही है। सरकार उस पर क्या कार्यवाई करेगी? इस पर बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उसका

गोपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी

जयपुर (विसं)। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने विधानसभा में आक्रोशित होने के बाद देर शाम सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। वीडियो में विधायक शर्मा ने कहा कि “आज प्रतिपक्ष के नेता ने मुझ को जिन चिन्तनों आरोपों में बांधकर संकेत किया, तो मैं सहन नहीं कर पाया और मैंने साबित करने की स्थिति में इस्तीफा दे देने तक की पेशकश की। ऐसा करते समय मैं सदन की मर्यादा भूल बैठा और उसके लिए मुझे आजीवन खेद रहेगा। इस बात को मैं पुरजोर शब्दों में दोहराना चाहता हूँ कि, मैं भारत माता, हिंदुत्व, ब्राह्मण, गौ, गायत्री, गीता और धरती माता के लिए जीवन भर समर्पित हूँ और अंतिम सांस तक समर्पित रहूंगा।”

गुनहवार खड़ा है। सदन में कांग्रेस विधायक पोस्टर लहराने लगे। जिस पर स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यहां पोस्टर दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आप प्लांटिंग करके आए हो, मुझसे फिर सहयोग की उम्मीद मत करना।

युवाओं के कौशल प्रशिक्षण पर रिव्यू मीटिंग 20 को

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज-उन्नति कार्यक्रम प्रदेश में कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का मजबूत मंच बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की सख्त मॉनिटरिंग का नतीजा है कि ‘डीडीयू-जीकेवाय’, राजविक्रम, सक्षम और समर्थ जैसी योजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। राज्य सरकार के संकल्प पत्र और बोते 2 वर्षों की बजट घोषणाओं के अनुरूप प्रदेश में नए आईआईटी केन्द्र खोला तथा केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार बीओसीडब्ल्यू निधियों से श्रमिकों के कौशल विकास के लिए पचपदरा में “सीआईपीईटी-सीएसटीएस” सेंटर की स्थापना तथा ऊर्जा कौशल विकास परिसर की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग आगामी 20 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली रिव्यू मीटिंग में इन तमाम मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखेगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने राजस्थान में चुनाव से पूर्व संकल्प पत्र में कहा था कि 100 आई.टी.आई. (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर) बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने बोते 2 वर्ष में 20 आईटीआई का प्रावधान बजट में किया था, परंतु अभी तक मात्र 1 बन पाया है।

‘बहानों की बेडियों से खुद को बाहर निकाले, सफलता कदम चूमेगी’

अर्जुन अवाडीं स्वीटी बूरा ने एस.के.आई.टी. कॉलेज के वार्षिकोत्सव तथा स्पोर्ट्स फेस्ट का उद्घाटन किया

जयपुर (कासं)। अपने बहानों को अपने लक्ष्य के मार्ग में मत आने दीजिए, सफलता किसी बहाने पर नहीं मिलती। ये कहना है साल 2023 की महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन-2023 अर्जुन अवाडीं स्वीटी बूरा का। वे सोमवार को स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एसकेआईटी) में सालाना एनुअल कल्चरल फेस्ट प्रवाह-2026 के उद्घाटन के सत्र में स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही थीं। छात्रों को उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बताया और कहा कि हमेशा कर्म पर विश्वास रखें और अपने जुनून को बरकरार रखें तो सफलता जरूर मिलेगी। इस अवसर पर समारोह के चीफ गेस्ट आरटीयू कोटा के वाइस चांसलर प्रो. निमित रंजन चौधरी भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रो निमित रंजन चौधरी ने विद्यार्थियों को अपने सम्पूर्ण विकास पर केंद्रित रहने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद, तीन दिवसीय इंटर-कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्ट ‘आवेग-2026’ का शुभारंभ हुआ। इस भव्य उद्घाटन समारोह में चेयरमैन सूरजाराम मील, वाइस चेयरमैन अनिल बाफना, डायरेक्टर जयपाल मील, डायरेक्टर अकादमिक प्रो. एस.एल. सुराना, रजिस्ट्रार रचना मील, डीन प्रो. आर.के. जैन, प्रिंसिपल रमेश कुमार पंचार एवं प्रवाह कन्वीनर डॉ बी एल शर्मा उपस्थित रहे। प्रवाह के खेल महाकुम्भ में पूरे राज्य के 40 से अधिक कॉलेजों के स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। फेस्ट के पहले दिन बैडमिंटन,



शतरंज, कैरम, रस्साकशी, कबड्डी, लॉन टेनिस, बॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल सहित कई खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं। स्पोर्ट्स फेस्ट का संचालन अजीत सिन्हा, महेंद्र कुमार बेनीवाल, चंदन कुमार और अमृता भंडारी के नेतृत्व में किया जा रहा है।

एसओजी की दबिश में पांच डमी परीक्षार्थी गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में डमी परीक्षार्थियों के जरिए चयन कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी की टीमों ने अंडमान-निकोबार, कोलकाता, जयपुर, कोटा और जालौर सहित

छह स्थानों पर एक साथ दबिश देकर 5 डमी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक संदिग्ध एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया गया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि डमी परीक्षार्थियों में महेश कुमार बिश्नोई (एमबीबीएस छात्र,

जयपुर), महिपाल बिश्नोई (एमबीबीएस छात्र, कोटा), सहोदाम (एमबीबीएस छात्र, पोर्ट ब्लेयर), हनुमानाराम (राजकीय अध्यापक) व निवास कुंआड़ा (राजकीय अध्यापक) शामिल हैं। एक अन्य संदिग्ध एमबीबीएस छात्र प्रिंस कोलकाता को हिरासत में लेकर जयपुर लाया जा रहा है।

राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से बम ब्लास्ट की धमकी



जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जयपुर पीठ के परिसर में एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। हर बार की तरह इस बार भी हाईकोर्ट प्रशासन के ईमेल पर समान पैटर्न में धमकी भरा मेल भेजा गया है। मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी और मुकदमों की सुनवाई एक घंटा बाद में शुरू करने का निर्णय लिया। सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारी बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ हाईकोर्ट परिसर पहुंचे। सुरक्षा दस्तों की ओर से हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की गई। हालांकि इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

हाईकोर्ट चौकी प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि बम की सूचना मिलते ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की ओर से पूरे हाईकोर्ट परिसर के चचे-चप्पे की जांच की गई। वहीं हाईकोर्ट के मुख्य परिसर से न्यायिक कर्मचारियों, अधिकारताओं व पक्षकारों को बाहर

निकाला गया। मौके पर किसी भी अनहोनी ने निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस तैनात की गईं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा के माफ़ूल इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहां अब तक कई बार बम ब्लास्ट के मेल मिल चुके हैं। जांच एजेंसियां अभी तक यह तक मालूम नहीं कर पाई है कि मेल कहां से आया है। हर बार मेल मिलने के बाद मुकदमों की सुनवाई बीच में बंद कर दी जाती है और कोर्ट परिसर खाली करा लिया जाता है। जिससे एक ओर भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित होती है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन को सबसे पहले गत वर्ष 31 अक्टूबर को बम विस्फोट की पहली धमकी मिली थी। इसके बाद 5 दिसंबर को दूसरी धमकी दी गई। वहीं 8 दिसंबर से लगातार चार दिनों तक बम ब्लास्ट को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन को मेल भेजे गए। इसके बाद गत छह फरवरी को ब्लास्ट की धमकी दी गई।